वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) आठवीं योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों की कवरेज बढ़ाने के लिए वर्तमान योजनाओं में संशोधन किया है और नई योजनायें आरंभ की गई हैं । इसके अतिरिक्त योजनाओं को पुन: तैयार किया गया है और नई योजनाएं इस प्रकार तैयार की गई हैं ताकि सहकारी क्षेत्र में शामिल न किए गए बुनकरों को भी उनका लाभ मिल सके ।

(ग) सरकार ने सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित योजनाओं का मूल्यांकन करने और आठवीं योजना में इनका कार्यान्वयन करने/इन योजनाओं में संशोधन आदि के लिए सुझाव देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा बुनकरों को सहकारी समितियों के रूप में संगठित किया जाना

1082. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकर देश भर में बिखरे हुए हैं और उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केवल 30 प्रतिशत बुनकर ही सहकारी समितियां बना कर संगठित हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन बुनकरों के असंगठित होने के कारण इन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के बुनकरों को संगठित करने तथा उन्हें सहकारिता आन्दोलन के अंतर्गत लाने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा बुनाई एक घरेलू कार्यकलाप है और अधिकांश बुनकर ग्रामों में रहते हैं । इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ही हथकरघा क्षेत्र के विकास की योजनायें तैयार की गई हैं ।

(ख) वर्ष 1987-88 में की गई हथकरघा गणना के अनुसार 20.29 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाया गया है तथा 4.15% बुनकर राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अंतर्गत लाए गए हैं ।

(ग) सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनायें सभी बुनकरों के लिए उपलब्ध हैं चाहे वे सहकारी क्षेत्र में हों अथवा उससे बाहर । ऐसी योजनाओं में बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण, डिजाइन आदि की आपूर्ति शामिल है । थ्रिफ्ट फंड योजना जो सातवीं योजना के दौरान केवल सहकारी क्षेत्र के बुनकरों के लिए ही उपलब्ध थी, में संशोधन किया गया है ताकि सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को भी इसका लाभ मिल सके और यह छूट 1991-92 से उपलब्ध है । वर्ष 1992-93 में लागू की गई समूह बीमा योजना सहकारी और गैर-सहकारी क्षेत्र के बुनकरों के लिए उपलब्ध है । 1991-92 में आरंभ की गई प्रोजेक्ट पैकेज योजना भी सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को उपलब्ध है । इसी प्रकार कार्यशाला-सह-आवास योजना भी सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को उपलब्ध है ।

(घ) तथापि सरकार सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को भी इन योजनाओं का लाभ दे रही है लेकिन हथकरघा बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाने के प्रयत्न जारी हैं । प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिए हथकरघा बुनकरों को ऋण सहायता देने की सातवीं योजना में जारी योजना 1992-93 में भी जारी है । वर्ष 1991-92 में आरंभ और चालू वर्ष में भी लागू निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी

नामों योजना में हथकरघा बुनकरों के सहकारीकरण पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष 1992–93 में भी लागू प्रोजेक्ट पैकेज योजना में सहकारीकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।

Review of the Policy of Export of Cotton/Cotton Yarn

1083. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to review the policy of exporting cotton/cotton yarn;

(b) whether the prices of cotton/cotton yarn are increasing at present; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) No, Sir.

(b) The prices of certain varieties of cotton/cotton yarn have shown a slight upward movement recently.

(c) while the slight upward movement in cotton prices can be attributed to absence of rains in certain parts of the country, the upward movement in cotton yarn prices is due to the upward movement in cotton prices and the general price rise.

Centre's Intervention to meet the demand of Cotton Growers in Andhra Pradesh

1084. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there was any demand from the Chief Minister of Andhra Pradesh for the intervention of Centre to meet the demands of cotton growers in Prakasam and Guntur District; and

(b) if so, what are the details thereof and what steps have been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) The problem of growing stocks of cotton with the farmers in Andhra Pradesh and particularly in Guntur and Prakasam Districts and their disposal was raised by the Chief Minister of Andhra Pradesh also.

The Cotton Corporation of India has already purchased about 1.93 lakh bales in Andhra Pradesh constituting 10.45 per cent of the production in Andhra. In Guntur and Prakasam over 45,000 bales have been purchased so far at a cost of Rs. 41 crores. Cotton Corporation of India is in the market and has offered to purchase MCU-5 variety of fair average quality at Rs. 1300 per quintal and FAQ JKHY-1 at Rs. 1200 per quintal.

Prevailing Prices of Cotton in Andhra Pradesh

1085. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state the weekly figures of the ruling prices of cotton in Andhra Pradesh since the beginning of the season?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GTHLOT): A Statement is attached.